

भारत, बांग्लादेश यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा होगी

ढाका, 7 सितंबर (भाषा)।

भारत और बांग्लादेश इस हफ्ते सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर चर्चा कर सकते हैं। ये सेवाएं 2024 में बांग्लादेश में हुई हिंसक अशांति के बाद से बंद हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री शेष हसीना की सरकार गिर गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश रेलवे के अधिकारी आज से ढाका में भारतीय अधिकारियों के साथ दो दिन की बैठक करेंगे। इसमें मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस सेवाओं को फिर से शुरू करने और एक नया रेलमार्ग शुरू करने की संभावना पर चर्चा होगी। अधिकारी ने कहा कि हम कल से शुरू होने वाली आइजीआरएम में मैत्री, बंधन व मिताली एक्सप्रेस जैसी रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। मैत्री एक्सप्रेस ढाका की कोलकाता से जोड़ती है, बंधन एक्सप्रेस खुलना को कोलकाता से जोड़ती है जबकि मिताली एक्सप्रेस पहले ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती थी।

उत्तराखंड : नीट में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कोटे की सीटों पर फर्जीवाड़ा नौ में से सात सीटें अयोग्य छात्रों को आबंटित

जनसत्ता संवाददाता देहरादून 7 सितंबर।

उत्तराखंड नीट में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी राज्य कोटे की सीटों के आवंटन को लेकर पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बातें सामने आई है। अकेले स्वतंत्रता सेनानी कोटे की 9 में से 7 सीटें अपात्रों को आवंटित कर दी गयीं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रकरण की निदेशक स्तर से जांच करवाई जा रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नीट के प्रथम चरण की काउंसिलिंग करवाने वाले उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने अपनी साइट पर स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कोटे के तहत आवेदन करने वाले 24 आवेदकों की जो सूची डाली है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से श्रीलंका के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 सितंबर।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आठ से 10 सितंबर तक श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सिंह अपनी यात्रा के दौरान श्रीलंका के नेतृत्व से परामर्श करेंगे और कोलंबो में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगे। वे रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि सिंह की श्रीलंका यात्रा पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में, जिनमें मजबूत समुद्री और रक्षा साझेदारी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध और बहुआयामी साझेदारी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग तथा मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है।

होर्मुज जलमार्ग में वर्जित क्षेत्र बनाएगा ईरान तेहरान बना रहा योजना, जहाजों पर रखेगा निगरानी

काहिरा, 7 सितंबर (एपी)।

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने रविवार को कहा कि तेहरान होर्मुज जलमार्ग के बाहर एक 'प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र' घोषित करने की योजना बना रहा है। इस क्षेत्र का उद्देश्य उन जहाजों को रोकना था उन पर निगरानी रखना होगा, जिनके बारे में ईरान को संदेह है कि वे होर्मुज जलमार्ग से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं।

ईरान के सरकारी प्रसारक से बातचीत में रेजाई ने यह बात कही। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उनके इस बयान से एक दिन पहले अमेरिका ने तीन ईरानी तेल

घोषणा

सर्वेक्षण : लखनऊ की हवा सबसे स्वच्छ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 7 सितंबर।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सोमवार को देश के शहरों और निगमों के वाडों के लिए 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2026' की घोषणा की। इन पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। वहीं, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को सातवां और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 21वें स्थान से संतोष करना पड़ा।

देश में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लखनऊ को 198 अंकों के साथ पहला स्थान मिला। सूची में दूसरे, तीसरे और

इस्तीफे के बाद मिलने वाली सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 सितंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने उन संवैधानिक पदाधिकारियों जिनमें जज भी शामिल हैं, को इस्तीफे के बाद मिलने वाली सुविधाओं और अन्य लाभों पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका में मांग की गई कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हटाने की कार्रवाई से बचने के लिए कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देते हैं, उन्हें कोई विशेष सुविधा, भत्ता, आवास या अन्य लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मांग की है कि यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी अपने खिलाफ हटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए इस्तीफा देता है तो उसे इस्तीफे के बाद सुविधा, भत्ता, लाभ या अन्य अधिकार का हकदार नहीं माना जाए।

याचिका में ऐसी किसी भी व्यवस्था को

याचिका में मांग की गई कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हटाने की कार्रवाई से बचने के लिए कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देते हैं, उन्हें कोई विशेष सुविधा, भत्ता, आवास या अन्य लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, जो कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले संवैधानिक पदाधिकारी को केवल हटाने की कार्रवाई से बचने के कारण ये सुविधाएं देती हो। इसके तहत केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस्तीफा देने वाले किसी संवैधानिक पदाधिकारी को याचिका लंबित रहने के दौरान कोई विशेष सुविधा या लाभ न दिया जाए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च संवैधानिक पद अपने साथ कार्यकाल पूरा करने की अलिखित संवैधानिक जिम्मेदारी लेकर आता है। किसी पदाधिकारी के लिए हटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए इस्तीफा देना न तो संविधान की भावना के अनुरूप है और न ही वांछनीय।

नहीं लगाया जा सकता। सबसे आश्चर्यजनक तो दून मेडिकल कालेज में आवंटित सीट को लेकर है। यहां के लिए एक अभ्यर्थी प्रॉजल ने प्रमाण पत्र का जो नंबर डाला है वह जारी भी नहीं हुआ है। और उसके लिए आवेदन किसी शंकुतला सजवान ने किया है। फिर भी प्रॉजल को सीट आवंटित कर दी गई है।

जिन्हें कोटे का लाभ मिला है उनमें से अधिकांश ने 10वीं और 12वीं बिहार, उत्तरप्रदेश यानी राज्य से बाहर दूसरे प्रदेशों से की है। अन्य अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड कोटे के तहत सीट का दावा किया है उनमें से चार तो एक ही सेनानी के कथित उत्तराधिकारी हैं। जिनको अलग-अलग कालेजों में सीटें आवंटित की गई है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कोटे के तहत सरकारी कॉलेजों की सीटों पर अपना दावा पेश किया था।

नेपाल बाढ़ : मृतकों की संख्या बढ़कर 1,355 हुई, 5,000 लोग अब भी लापता

काठमांडो, 7 सितंबर (भाषा)।

नेपाल में अचानक आयी विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित इलाकों से और शव बरामद किए जाने के बाद सोमवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 1,355 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय विपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने बताया कि बचाव दल अब भी 4,996 लोगों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें कम से कम 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 13,396 लोगों को बचाया जा चुका है।

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को हिमस्खलन के कारण अचानक भोटेकोशी नदी में आयी बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई है। चीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक इस आपदा से चीन नियंत्रित तिब्बत में भी कम से कम 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 से अधिक लोग अब

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को हिमस्खलन के कारण अचानक भोटेकोशी नदी में आयी बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कस्बों तथा गांवों में भारी तबाही मचाई है।

भी लापता हैं। एनडीआरआरएमए के अनुसार, चितवन जिले से 363 शव, नवलपरासी पश्चिम से 221, नवलपरासी पूर्व से 222 और नुवाकोट से 197 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह, रसुवा से 169, गोरखा से 75, धादिंग से 70 और तनहू से 38 शव बरामद किए गए हैं।

एनडीआरआरएमए के मुताबिक सोमवार तक केवल 98 शवों की पहचान की गई और उन्हें उनके परिवारों को सौंपा गया। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि पानी के साथ बहकर आए कई शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हैं, या फिर उनके केवल कुछ हिस्से ही मिल पाए हैं।

थे। रेजाई ने कहा कि नए क्षेत्र की घोषणा आने वाले दिनों में की जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘यह क्षेत्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की सीमा से शुरू होगा, होर्मुज जलमार्ग की ओर बढ़ेगा और इस तर्फ से फारस की खाड़ी तक फैलेगा।

जो भी जहाज होर्मुज से गुजरने के इरादे से इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा और जिसकी पहचान हो जाएगी, उसे हमारी प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।' यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान कई सप्ताह से जारी अमेरिकी नाकाबंदी की सीमा क्षति जगह को मानता है। अमेरिका ने यह नाकाबंदी ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाने और तेहरान को अपना तेल बाहर भेजने से रोकने के लिए की है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से वृद्धाश्रम में सुविधाओं की रिपोर्ट मांगी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 7 सितंबर।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे वृद्धाश्रमों की स्थापना और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति के बारे में ताजा रिपोर्ट दाखिल करें। न्यायालय 2016 में दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें बुजुर्गों के कल्याण एवं संरक्षण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने डा अश्विनी कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

याचिका में प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने, वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त पेंशन देने और उनके लिए वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों को लागू करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के दौरान स्वयं



अपना पक्ष रख रहे कुमार ने पीठ से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों बुजुर्गों के अधिकारों एवं कल्याण से जुड़ा यह मामला वर्षों से लंबित है और न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए जाने के बावजूद इस पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय व्यापक सिद्धांत तय कर सकता है और उच्च न्यायालयों से उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा जा सकता है। केंद्र ने

मामले को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया लेकिन पीठ ने पहले सभी राज्यों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अद्यतन जानकारी मांगने का फैसला किया। पीठ ने कहा, ह्यअटानी जनरल आर. वेंकटरमणी सभी राज्यों के महाधिवक्ताओं को पत्र भेजकर उनसे वृद्धाश्रमों की स्थापना और उनमें उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सुविधाओं की स्थिति संबंधी ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहे।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.		
PUBLIC ANNOUNCEMENT		
MTE STRUCTURES LIMITED CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: U28994GJ2020PLC117076 <i>Our Company was incorporated on October 06, 2020 as "MTE Structures Private Limited, a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders at an Annual General Meeting held on September 30, 2024 and consequently the name of our Company was changed to "MTE Structures Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 06, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 150 of the Draft Red Herring Prospectus.</i>		
Registered Office: Plot No. 1063, Canal Road, Manjusar, Savli, Vadodara, Gujarat – 391775 India. Telephone: +91-6354869315; E-mail: cs@mtgroup.in ; Website: https://mtgroup.in/ Contact Person: Mrs. Jinal Bhavik Shah, Company Secretary & Compliance Officer; Corporate Identity Number: U28994GJ2020PLC117076		
OUR PROMOTERS: MR. HIREN ARVINDBHAI PATEL, MR. JANAK BHARAT AMIN AND MR. TEJASKUMAR PATEL		
"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM BSE LIMITED ("BSE")."		
THE OFFER		
INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 43,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF MTE STRUCTURES LIMITED (THE "COMPANY" OR "MTE STRUCTURE" OR "ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [-] MILLION ("PUBLIC OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UPTO 37,06,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UPTO 2,18,000 EQUITY SHARES BY MR. HIREN ARVINDBHAI PATEL, UPTO 2,18,000 EQUITY SHARES BY MR. JANAK BHARAT AMIN AND UPTO 2,18,000 EQUITY SHARES BY MR. TEJASKUMAR PATEL ("THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AGGREGATING UPTO 6,54,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [-] MILLION OUT OF WHICH [-] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [-] MILLION WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF [-] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [-] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [-] MILLION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE [-] % AND [-] % RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.		
THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN [-] EDITION OF [-] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [-] EDITION OF [-] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND GUJARATI EDITION OF [-], A GUJARATI REGIONAL NEWSPAPER (GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE IN ACCORDANCE WITH SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").		
In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/Offer Period for a minimum of One Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank as applicable.		
This offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 (1) and 253 (2) of the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, wherein not more than 50.00% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company and the selling shareholders in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under- subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, other than Anchor Investors, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from QIB Bidders is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, the SEBI ICDR Regulations read with SEBI ICDR (Amendment) Regulations, 2025, states that not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size. Not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors of which one-third of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots as equivalent to not more than ₹ 1.00 million and two-thirds of the Non-Institutional Portion will be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1.00 million and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Portion. Subject to the availability of shares in non-institutional investors' category, the allotment to each Non-Institutional Investors shall not be less than the minimum application size in Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XII of the SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025. All Potential Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Offer by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, please refer to the chapter titled "Offer Procedure" on page 233 of this Draft Red Herring Prospectus.		
This public announcement is being made in compliance with the Regulation 247(2) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification dated March 03, 2025, and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the offer and DRHP dated September 04, 2026 which has been filed with the BSE SME Platform of BSE Limited.		
Pursuant to SEBI (ICDR) (Amendment) Regulations, 2025 on March 03, 2025 and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME companies, for fulfilling all additional eligibility criteria, the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the BSE at https://www.bseindia.com/ and the website of the Company at https://mtgroup.in/ and at the website of BRLM I.e. GYR Capital Advisors Private Limited at https://gyrcapitaladvisors.com. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with BSE SME.		
Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer including the risks involved. The Equity Shares issued in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited of the section titled "Risk Factors" beginning on Page 23 of this Draft Red Herring Prospectus.		
Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the Draft Red Herring Prospectus. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of BSE ("BSE SME"). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see "Capital Structure" beginning on page 64 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 150 of the Draft Red Herring Prospectus		
BOOK RUNNING LEAD MANAGERS GYR Capital Advisors <i>(Joint Lead Manager)</i> GYR CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED CIN: U67200GJ2017PTC096908 SEBI Registration Number: INM000012810 Address: 428, Gala Empire, Near JB Tower, Drive in Road, Thaltej, Ahmedabad – 380 054, Gujarat, India. Telephone No.: + 91 87775 64648 Website: www.gyrcapitaladvisors.com Email ID: mte_ips@gyrcapitaladvisors.in Investor Grievance Email: investors@gyrcapitaladvisors.com Contact Person: Mr. Mohit Baid/ Ms. Heena Parwani	REGISTRAR TO THE ISSUE MUFG MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED CIN: U67190MH1999PTC118368 SEBI Registration Number: INR0000004058 Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, Lai Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India. Telephone: + 91 8108114949 E-mail ID: mtestructures.smeipo@in.mpmgs.mufg.com Website: www.linkintime.co.in Investor Grievance Email: mtestructures.smeipo@in.mpmgs.mufg.com Contact Person: Shanti Gopakrishnan	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER MTE Mrs. Jinal Bhavik Shah Address: Plot No. 1063, Canal Road, Manjusar, Savli, Vadodara, Vadodara, Gujarat, India, 391775 Tel.: + 91 63548 69315 E-mail: cs@mtgroup.in Website: https://mtgroup.in/ Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Managers or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.		
MTE STRUCTURES LIMITED ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS Sd/- Mrs. Jinal Bhavik Shah Company Secretary & Compliance Officer		
Disclaimer: MTE Structures Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on September 04, 2026. The Draft Red Herring Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bseindia.com/ and is available on the websites of the BRLM at https://gyrcapitaladvisors.com/offer-documents/ and also on the website of the Company https://mtgroup.in/. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Draft Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for making any investment decision. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulations under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.		